

जी.एस.टी. 2.0 (रिफॉर्म्स का नया दौर) केवल आशा पर निर्भर नहीं है

वित्त मंत्री आशा कर रही हैं कि इन रिफॉर्म्स के कारण रोजमर्रा का सामान सस्ता होगा, और डिमाण्ड (मांग) बढ़ेगी

-अंजन गंध-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-

नई दिल्ली, 4 सितम्बर। जीएसटी काउन्सिल द्वारा किए गए सुधार पूरे देश के लिए एक बड़ा बदल जैसा कदम है। यह कदम न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्यों के बजट को भी बदल करने वाला अहम कारबने वाला। माल और सेवा कर यानी जीएसटी ने सभी अप्रत्यक्ष करों (इनडाक्यूसेज) को गिराकर एक साक्षा कर दिया बनाया था और अब यह केंद्र व राज्यों दोनों को कुल आय का बड़ा हिस्सा है।

दरअसल, जीएसटी की दरों में व्यापक और क्षेत्रों को बदलने की कोशिश के पांचे तरफ हैं। सबसे पहले, यह कर दरों की श्रेणियों को साल बनाने और घटाने के बाद को पूरा करता है।

यह सुधार, 2017 में जीएसटी

लागू करने समय शुरू है व्यापक कर सुधारों का बाहर होगा। इस समय देश

में केंद्र और राज्यों की कई अलग-

अलग कर व्यवस्थाएँ थीं जिन्हें

मिलाकर एक समान "कर प्रणाली"

यानी जी.एस.टी., बनाई गई।

- विदेश में (विशेषकर अमेरिका में) ऊची टैरिफ के कारण भारतीय सामान के निर्यात को धक्का लगेगा। वित्त मंत्री चाहती है कि विदेशों में मांग घटने से व्यापार में आई कमी की भरपाई है, देश में स्थानीय खपत बढ़ने से पूरी की जा सकेगी।
- टैक्स घटा कर, "इन्टर्नल डिमाण्ड" बढ़ाने का फार्मूला कई देश पहले ही अजमा चुके हैं। उदाहरण के लिये, अमेरिका में भी राष्ट्रपति रीगन की सरकार ने स्थानीय टैक्स काफी घटाये थे, तथा इससे देश में "इन्टर्नल डिमाण्ड" आंकलन से भी ज्यादा बढ़ी थी, और अमेरिका की इकॉनमी के बारे-न्यारे हो गये थे।
- पर अगर भारतीय उद्योगपतियों ने बढ़ती डिमाण्ड की पूर्ति के लिये, नया इन्वेस्टमेंट करके औद्योगिक क्षमता नहीं बढ़ाई, तो सप्लाई की पूर्ति नहीं कर पायेंगे और मंहगाई बढ़ेगी, और इकॉनमी में उल्टा चक्रकर घूमने लगेगा और अगर इकॉनमी इस दूष्यरचना में फंस गई तो उससे उबरना बहुत मुश्किल होगा।

उस समय वादा किया गया था कि धोरे इन्हें दो स्लैब में समेता जाएगा। केवल दो टैक्स स्लैब होंगे, लेकिन वर्तमान सुधार उसी दिशा में कदम है व्यवहारिक कारों से चार स्लैब लागू। जिससे अब 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और एक अलग, 40

प्रतिशत का "सिन टैक्स" शामिल है।

औसतन, जीएसटी केंद्र और राज्यों की कुल आय का लगभग 44 प्रतिशत है, तथा राज्यों की आय में इकाका हिस्से और भी अधिक है। इसलिए दोनों में बदलाव से राज्यों की विविध रिस्ट्रिक्शन केंद्र से ज्यादा प्रभावित हो सकती है। चूंकि जीएसटी की दरों के काउन्सिल तय करती है और न तो केंद्र और न ही राज्य इन्हें अकेले बदल सकते हैं, इसलिए ये घोषणाएँ एक ठोस व स्थाई ढांचा देती हैं जिसके भीतर बजट बनाना अनिवार्य होगा।

ए.जी.एस.टी. सुधारों की घोषणा से बजट बनाने के लिए एक अधार तय हो गया है।

जीएसटी 2.0 कहलाने वाले इस स्लैब सुधार की घोषणा युरोपन बजट घोषणाओं जैसी लागू, जहाँ कर में बदलाव के असर से रोजपानी की चीजों की कीमतें ऊपर नीचे होती थीं, सिगरेट महंगी, बीजील सप्लाई सकती है। जीएसटी के अद्वेलना हुई है तो कोनकीनी प्रावधारों का सहारे ले सकती है। जरियाने की कुमार उपरान की एकलपती ने ये अदेश महंगी अपनी पारीक और इंद्र वर्मा की याचिका में उनके मौलिक अधिकारों की अद्वेलना हुई है तो कोनकीनी प्रावधारों की अवैध कटाई की जाए ही।

जीएसटी के बाद जीएसटी की घोषणा दो हुए कठोर, "एक गंभीर अदालत ने याचिका की घोषणा की बीच तीन विधायिकों ने सरकार पर सुनवाई करते हुए दिए।" सुनवाई के दौरान, न्यायिक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जमानती अपराध पर महिला आरोपियों को 43 दिन जेल में रखना खेदजनक

जयपुर, 4 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानती अपराध होने के बावजूद, महिला आरोपियों का जमानत प्राविधिक निरस जेल भेजने तथा उन्हें 43 दिन तक जेल में रखने पर खेद जागाया है। इसके साथ ही, अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय की ओर से पेश याचिकाएँ से असंतुष्ट होते हुए रोजस्ट्रार को आदेश दिए हैं कि वे प्रकरण की आवश्यकता नहीं है।

हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारी मशीनी अंदाज में जमानत प्रार्थना पत्र नहीं निपायाएँ।

जानकारी जिले के गार्डिन जन जक को दें। वाही अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वे संबंधित जांच अधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांग कर आगामी कार्यवाही में देखा गया है। एक गंभीर अदालत ने याचिका की घोषणा की बीच तीन विधायिकों ने उनके मौलिक अधिकारों की अद्वेलना हुई है तो कोनकीनी प्रावधारों का सहारे ले सकती है। जरियाने की कुमार उपरान की एकलपती ने ये अदेश महंगी अपनी पारीक और इंद्र वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, न्यायिक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने माना उत्तरी राज्यों में भारी बाद का प्रमुख कारण पेड़ों की अवैध कटाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मीडिया रिपोर्ट्स में बाद में लकड़ी के बड़े-बड़े लट्ठे बहते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लगता है पहाड़ों पर पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवर्ड और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बीच ने इस बारे में सॉलिसिटर जनरल तुशार मेहता को संबोधित करते हुए कहा, "ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठे दिख रहे हैं इससे लगता है पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है।"

एस जी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट का आश्वासन दिया कि वे इस बारे में जल्दी से जल्दी पर्यावरण मंत्रालय व राज्यों के मुख्य सचिवों से बात करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय, जलशक्ति विभाग, नैशनल डिझास्टर मैनेजमेंट अथोरिटी, नैशनल हाइवे ज़ेरो एंड रोड अथोरिटी और जम्मू कश्मीर व उत्तराखण्ड सरकार को आश्वासन दिया कि वे इस बारे में जल्दी से जल्दी पर्यावरण मंत्रालय व राज्यों के मुख्य सचिवों से बात करेंगे।

(एनडीएमए) तथा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और जम्मू-कश्मीर की पीठ ने गुरुवार के विमाचल प्रदेश में बाद के दौरान बहती लकड़ियों के बीच फेंजे जाएं। "एक गंभीर अदालत ने याचिका की घोषणा की है।" मीडिया रिपोर्ट्स में देखा गया है कि बाद में भारी मात्रा में लकड़ी के लट्ठे बहते हुए नजर आए। प्रथम दृष्टिया एस प्रतीक बात होती है कि पहाड़ों में पेड़ों की अवैध कटाई की जाए ही।

पीड़ ने केंद्र सरकार को -पर्यावरण मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से - और साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), सरकारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनडीएमपी) को कहा है। इसके बाद इस मामले की आगे सुनवाई होगी।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर.गवर्ड ने गुरुवार के विमाचल प्रदेश में बाद के दौरान बहती लकड़ियों के बीच फेंजे जाएं। एक गंभीर अदालत ने याचिका की घोषणा की है।" मीडिया रिपोर्ट्स में देखा गया है कि बाद में भारी मात्रा में लकड़ी के लट्ठे बहते हुए नजर आए। प्रथम दृष्टिया एस प्रतीक बात होती है कि पहाड़ों में पेड़ों की अवैध कटाई की जाए ही।

(एनडीएमए) तथा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और जम्मू-कश्मीर की पीठ ने गुरुवार के विमाचल प्रदेश में बाद के दौरान बहती लकड़ियों के बीच फेंजे जाएं। "एक गंभीर अदालत ने याचिका की घोषणा की है।" मीडिया रिपोर्ट्स में देखा गया है कि बाद में भारी मात्रा में लकड़ी के लट्ठे बहते हुए नजर आए। प्रथम दृष्टिया एस प्रतीक बात होती है कि पहाड़ों में पेड़ों की अवैध कटाई की जाए ही।

मुख्य न्यायाधीश ने विचार व्यवहार के संपर्क में नोटिस भारी करते हुए दिए।

मुख्य न्यायाधीश ने विचार व्यवहार के संपर्क में नोटिस भारी करते हुए दिए।

मुख्य न्यायाधीश ने विचार व्यवहार के संपर्क में नोटिस भारी करते हुए दिए।

मुख्य

